State Electricity Boards	1985-86
13. Tamil Nadu	27 88
14. Uttar Pradesh	(1.1)
15. West Bengal	(29.91)
16. Assam	(115.28))
17. Meghalaya	(2.43)
18. Jammu & Kashmir	Not available
CENTRAL SECTOR	
Profit after tax	
1 National Thermal Power Corporation	182.95
2. National Hydroelectric Power Corpn.	18.79
PRIVATE SECTOR	
After Statutory Appropriation but before payment of dividends.	
1. Ahmedabad Electricity Company Ltd. (A.E. Co.)	5.38
2. Tata Power Company Ltd. (Trombay)	2 81
3. Calcutta Electric Supply Corporation (CESC)	Not available

Electricity requirement of Rajasthan

1613. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what is the present consumption and requirement of electricity in the State of Rajasthan;

(b) what was the total electricity generated in Rajasthan during the last three years; and

(c) what is the quantum of electricity which the Central Government propose to supply to the rural areas of Rajasthan for irrigation purposes during the current financial year?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) During the month of October, 1987 the energy availability in Rajasthan was 653 million units as against the requirement of 736 million units.

(b) The total energy generation during 1984-85, 1985-86 and 1986-87 in the State was 3028 million units, 3326 million units and 3637 million units respectively.

(c) Supply to various categories of consumers is decided by the State Authorities keeping in view the position regarding demand and availability of power in the State, from time to time States including Rajasthan have been requested to accord high priority in the matter of power supply to agricultural sector. Agricultural consumers were supplied power for about 8 hours per day during October, 1987 in Rajasthan.

उत्तर प्रदेश के गांवों में विद्युतीकरण

1614. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या ऊर्जा मंत्री 9 नवम्बर, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 129 के दिये गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की

कृपा करेंगे कि 31 अक्तूबर, 1987 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांवों में बिजली की व्यवस्था कर दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : उत्तर प्रदेश में 31-10-1987 को स्थिति के अनुसार कुल 72,701 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

Discussions with Italy for strengthening Eenergy Sector

1615. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether any discussions have recently been held with Italy for strengthening cooperation between the two countries in the energy sector; and

(b) if so, what are the details of the discussions held?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b) During recent discussions, the visiting Italian delegation expressed interest in strengthening cooperation between the two countries in the energy sector. It was agreed that the possibilities of identifying specific areas of cooperation should be further explored.

एल पी जी विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतें

1616. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैस बर्नरों/हाट प्लेटों की खरीदारी के संबंध में एल०पी०जी० विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त हुई राज्यवार शिकायतों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित शिकायतों में से कितनी शिकायतें लंबित पड़ी हुई है और कितनी शिकायतें विचाराधीन हैं ; और

(घ) लंबित तथा विचाराधीन शिकायतों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1984 से 1986 तक के दौरान वितरकों द्वारा गैस बर्नरों/हाट प्लेटों को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को मजबूर करने के बारे में तेल कम्पनियों के पास कुल लगभग 2260 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनका राज्यवार विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ख) एल० पी० जी० वितरकों के विरुद्ध तेल कम्पनियों में प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक होने पर तत्काल जांच की जाती है और विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अधीन दोषी वितरक के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है जो चेतावनी पत्र जारी करने से लेकर कुछ मामलों में वितरणशिप को समाप्त करने तक होती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जबरन हाट प्लेटों की बिक्री के संबंध में शिकायतें

राज्य	प्राप्त शिकायतें
1. आन्ध्र प्रदेश	95
2. असम	—
3. बिहार	43